



बढ़ती नगरीकरण की समस्याएँ

Dr. Panmal Pahariya

Associate Professor, Dept. of Geography, Govt. College, Tonk, Rajasthan, India

सार

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या की 26 प्रतिशत आबादी अर्थात् 21.70 करोड़ जनसंख्या नगरों में निवास करती है। अगर हम सिर्फ पिछले 40 वर्षों की स्थिति पर गौर करें तो पाते हैं कि उस समय कुल जनसंख्या के 12 प्रतिशत लोग ही शहरों में निवास करते थे। लेकिन स्वतन्त्रता के बाद जैसे-जैसे आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की गति तीव्र हुई, वैसे-वैसे नगरों की संख्या तथा उनमें निवास करने वाली जनसंख्या दोनों में वृद्धि हुई, जो सारणी-1 से स्पष्ट है। जहाँ तक भारत में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत का प्रश्न है, यह निश्चित रूप से माना जा सकता है कि यह विकसित देशों की तुलना में काफी कम है, लेकिन अगर नगरों में निवास करने वाली कुल जनसंख्या पर दृष्टिपात करें तो हम पाते हैं कि यह संख्या कई विकसित देशों की कुल जनसंख्या से भी अधिक है।

परिचय

नगरीकरण की प्रवृत्ति

भारतीय जनगणना विभाग द्वारा भारतीय नगरों को जनसंख्या के आधार पर छह भागों में विभाजित किया गया है:

प्रथम वर्ग	- 1 लाख से अधिक जनसंख्या
द्वितीय वर्ग	- 50,000-99,999
तृतीय वर्ग	- 20,000-49,999
चतुर्थ वर्ग	- 10,000-19,999
पंचम वर्ग	- 5,000-9,999
षष्ठम वर्ग	- 5,000 से कम

अगर हम भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति (सारणी-2) पर गौर करें तो पाते हैं कि प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वर्ग के नगरों की संख्या में वृद्धि काफी तीव्र गति से हुई है। चतुर्थ श्रेणी के नगरों में भी वृद्धि हुई है। लेकिन पंचम श्रेणी के नगरों में 1901 की तुलना में कमी आई। 1951 तक इस श्रेणी में वृद्धि हुई। उसके बाद घटते-घटते 1971 तक यह 623 तक पहुँच गई। 1981 में इसमें पुनः वृद्धि दृष्टिगोचर हुई, लेकिन 1991 में इसमें पुनः कमी आई। इसी तरह छठे वर्ग के कस्बों की संख्या में 1921 तथा 1981 को छोड़कर लगातार ह्रास की प्रवृत्ति जारी रही है।

कस्बों की संख्या में कमी का कारण व्यापक पैमाने पर बड़े नगरों की तरफ जनसंख्या का झुकाव एवं जनगणना विभाग द्वारा नगरों की परिभाषा में परिवर्तन करना है। भारतीय जनगणना विभाग द्वारा नगरों की परिभाषा में किए गए परिवर्तन के फलस्वरूप 1951-61 के दशक में पाँचवें वर्ग में 405 कस्बों तथा छठे वर्ग में 399 कस्बों को पुनः अवर्गीकृत कर ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तित कर दिया गया।



बड़े नगरों में जनसंख्या वृद्धि तथा उनकी संख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति 1991 तक जारी रही। वर्तमान समय में प्रथम वर्ग के नगरों में कुल नगरीय जनसंख्या का 65.20 प्रतिशत भाग निवास करता है (असम एवं जम्मू-कश्मीर को छोड़कर)। दूसरी तरफ चतुर्थ श्रेणी के कस्बों में मात्र 7.77 प्रतिशत एवं पांचवीं श्रेणी के कस्बों में 31.45 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या निवास करती है।[1]

यही प्रवृत्ति महानगरों के सम्बन्ध में भी देखने को मिलती है। 1901 में भारत में सिर्फ एक महानगरा (कलकत्ता) था। 1911 से 1941 तक यह संख्या 2 तक सीमित रही। 1951 में यह संख्या बढ़कर 5, 1961 में 7, 1971 में 9, 1981 में 12 तथा 1991 में 23 हो गई। 1981 से 1991 के दशक में इसमें लगभग दुगुनी वृद्धि हुई।

नगरीय जनसंख्या में वृद्धि के कई कारण हैं जिनमें मुख्य है- गाँवों से नगरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण। एक अन्य कारण नगरीय जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का है। बड़े नगरों या नगरीय समूह के चारों तरफ कालांतर में रेलवे कालोनी, विश्वविद्यालय परिसर, पत्तन क्षेत्र, सैनिक छावनी इत्यादि विकसित हो जाते हैं। इनमें कई बार तो ऐसी स्थिति भी देखने को मिलती है कि कुछ क्षेत्र नगरपालिका/नगर निगम के क्षेत्र से बाहर विकसित हो जाते हैं तथा गाँवों के राजस्व क्षेत्र में आते हैं। ऐसे क्षेत्र को जनगणना विभाग द्वारा बाह्य विकसित (आउट ग्राउथ) क्षेत्र के रूप में मान्यता दे दी जाती है तथा इसकी गणना भी कस्बों के साथ-साथ की जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों/शहरों में स्थानांतरण का कारण रोजगार का अभाव, कृषि भूमि पर अधिक दबाव, उत्पादकता में गिरावट, निम्न रहन-सहन इत्यादि है। इसी तरह नगरों में रोजगार के अधिक अवसर, मजदूरी की अधिक दरें, शहरों का चकाचौंधपूर्ण जीवन, शिक्षा प्राप्ति के अधिक अवसर इत्यादि कारक ग्रामीण जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।

इस तरह नगरीय जनसंख्या में वृद्धि के कारण कई तरह की समस्याएँ जन्म ले चुकी हैं जो धीरे-धीरे वीभत्स रूप धारण करती जा रही हैं। नगरों में उत्पन्न समस्याओं को निम्नांकित भागों में बाँटा जा सकता है:

1. पर्यावरणीय समस्या
2. आवास की समस्या
3. रोजगार की समस्या
4. अन्य सामाजिक समस्याएँ[2]

1. पर्यावरणीय समस्या: नगरीय केन्द्रों में जनसंख्या के लगातार बढ़ते रहने एवं औद्योगीकरण के फलस्वरूप पर्यावरण प्रदूषण तथा अवनयन की कई समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं। सबसे ज्यादा प्रदूषण वायु तथा जल में देखने को मिलता है।

महानगरों में प्रदूषण का मुख्य कारण वाहनों एवं औद्योगिक संस्थानों द्वारा निस्सृत विषैले रसायन हैं। जिनमें मुख्य है: सल्फर डाईऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा एवं नाइट्रस ऑक्साइड। एक सर्वेक्षण (नेशनल इन्वायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीच्यूट, नागपुर) के अनुसार 1990 में उद्योगों से निकलने वाले सल्फर डाईऑक्साइड की मात्रा 45,000 टन प्रति वर्ष थी, जो बढ़कर सन 2000 से 48,000 टन प्रतिवर्ष हो जाने की आशा है।

इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा 1980 में 1,40,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़कर 1990 में 2,65,000 प्रतिवर्ष हो गई थी तथा आशंका है कि सन 2000 तक यह मात्रा 4,00,000 टन प्रतिवर्ष हो जाएगी।

इसी तरह औद्योगिक नगरों में जाड़े के मौसम में तापीय प्रतिलोमन के समय कारखानों की चिमनियों से निस्सृत धूम्र एवं सल्फर के स्थिर वायु के साथ मिश्रण के कारण जानलेवा नगरीय धूम्र कोहरे की उत्पत्ति होती है।[3]

वाहनों से निकलने वाले धूम्र के साथ सीसा नामक तत्व भी निकलता है जिसका बुरा प्रभाव हमारे श्वसन-तंत्र पर पड़ता है। सल्फर डाईऑक्साइड गैस वर्षा के जल के साथ संयोग करके सल्फ्यूरिक अम्ल में परिणत हो जाती है। यह अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर पहुँचता है जिसके फलस्वरूप त्वचा कर्कटाबुद (कैंसर) की आवृत्ति में वृद्धि होती है।



सारणी-1

वर्ष	नगरों की कुल संख्या	नगरीय जनसंख्या
1951	2795	61,629,646
1961	2270	77,562,000
1971	2476	106,966,534
1981	3245	156,419,768
1991	3609	212,867,337
स्रोत: भारतीय जनगणना, 1991, सीरीज-1 असम एवं जम्मू-कश्मीर को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है।		

सारणी-2

भारत में विभिन्न श्रेणी के नगरों की संख्या

जनगणना	श्रेणी					
वर्ष	1	2	3	4	5	6
1901	24	43	130	390	744	479
1911	23	40	135	364	707	485
1921	29	45	145	370	734	571
1931	35	56	183	434	800	509
1941	49	74	242	498	920	407
1951	76	91	327	608	1124	569
1961	102	129	427	719	711	172
1971	148	173	558	827	623	147
1981	215	270	738	1053	739	229



1991	296	341	927	1135	725	185
स्रोत: भारतीय जनगणना, 1991, सीरीज-1						

इसी तरह बढ़ती नगरीकरण की प्रवृत्ति ने जल को भी काफी हद तक प्रभावित किया है। दिनों-दिन नगरों में पक्के आवासों की संख्या बढ़ती जा रही है जिससे वर्षा का जल रिसकर अंदर नहीं जा पाता है। फलस्वरूप धरातलीय जल-स्तर में कमी आ रही है।

महानगरों में स्थित कल-कारखानों द्वारा निष्कासित कचरे मुख्य रूप से नदी-नालों में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। इसके कारण नदियों का पानी भी पीने लायक नहीं रह गया है। दिल्ली के पास यमुना नदी मात्र एक नाला बनकर रह गई है। इसी तरह कानपुर में स्थित चमड़े के कारखानों के कारण गंगा नदी किसी कार्य के लिए भी उपयोगी नहीं रह गई है।[4]

महानगरों में ध्वनि प्रदूषण का स्तर भी काफी ऊँचा हो गया है। इनमें अबाध गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण स्वचालित वाहनों तथा अन्य ध्वनि प्रदूषकों में तेजी से वृद्धि हुई है। भारत के अधिकांश महानगरों में ध्वनि का स्तर 70-80 डेसीबल तक पहुँच गया है जिससे श्रवण-सम्बन्धी समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं।

2. आवास की समस्या: पर्यावरण के बाद सबसे महत्वपूर्ण समस्या आवास की है। यह समस्या आवास की गुणवत्ता एवं मात्रा दोनों में देखने को मिलती है। वर्तमान समय में भारत में 3 करोड़ 10 लाख आवासीय इकाइयों की कमी है जिसमें 206 लाख आवास की कमी ग्रामीण क्षेत्र में तथा 104 लाख शहरी क्षेत्र में है। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण सुविधायुक्त मकानों की मात्रा भी काफी कम है तथा सन 2000 तक लगभग 7 मिलियन आवासों की कमी की सम्भावना है। नवीनतम अनुमानों के अनुसार कुल नगरीय आबादी का 14.68 प्रतिशत झुग्गी-झोपड़ियों में निवास करता है। भारत के विभिन्न महानगरों की कुल नगरीय आबादी का एक बड़ा भाग झुग्गी-झोपड़ियों में निवास करता है जो नीचे की तालिका से स्पष्ट है:[5]

महानगर	कुल जनसंख्या का प्रतिशत
मुंबई	38.30
कलकत्ता	35.35
दिल्ली	30.19
चेन्नई	31.87
अहमदाबाद	26.16
बंगलौर	10.02
कानपुर	40.31
लखनऊ	38.83
स्रोत: हैण्डबुक आफ हाउसिंग स्टैटिस्टिक्स-1981, नेशनल बिल्डिंग आर्गनाइजेशन, नई दिल्ली।	



3. रोजगार की समस्या: जिस अनुपात में नगरों में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, उसी अनुपात में रोजगार में वृद्धि नहीं हो रही है। गाँवों से शहरों में आने वाले लोगों की अधिक संख्या के कारण उन्हें शहरों में कम मजदूरी पर कार्य करना पड़ता है जिससे सामाजिक अव्यवस्था बढ़ती चली जाती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण-शहरी स्थानांतरण में कमी आई है। इसका कारण ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों की सफलता मानी जाती है।[6]

अन्य सामाजिक समस्याएँ: इन उपरोक्त मुख्य समस्याओं के अतिरिक्त भी कई समस्याएँ हैं। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोग अधिकतर गरीब होते हैं, अतः पैसे की कमी के कारण वे अमीर लोगों की बस्तियों के किनारे झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। इन गरीब वर्ग के लोगों का शैक्षणिक स्तर भी निम्न होता है तथा नगरों की साफ-सफाई की व्यवस्था का बोध नहीं होने के कारण शहरी वातावरण उनके लिए संकटमय हो जाता है। यह संकट कभी-कभी विकराल रूप धारण कर लेता है। उदाहरण के तौर पर जनवरी, 1995 में दिल्ली की एक मध्यमवर्गीय कालोनी में गरीब लोगों के समूह ने वहाँ स्थित पार्क का उपयोग शौचालय के रूप में करना शुरू कर दिया। फलस्वरूप उत्पन्न हुए झगड़े में चार लोगों की मृत्यु हो गई तथा जान-माल का काफी नुकसान हुआ। यहाँ पर स्व. श्रीमती इंदिरा गाँधी की यह उक्ति कि 'गरीबी ही सबसे बड़ा प्रदूषण है', काफी प्रासंगिक होती है। इसके अतिरिक्त गरीबी एवं अमीरी की बढ़ती हुई खाई के कारण गरीब लोगों में अधिकाधिक पैसे की प्राप्ति के लिए आपराधिक भावना भी पनप उठती है जिससे शहरी जीवन तनावग्रस्त हो जाता है।

इस तरह हम देखते हैं कि भारत में बढ़ते नगरीकरण के कारण कई समस्याओं का जन्म हो चुका है। इन समस्याओं के पीछे मुख्य कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। अतः हमें सबसे पहले बढ़ती जनसंख्या को काबू में करना होगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। इसके लिए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के कई अवसर- जैसे नेहरू रोजगार योजना, ट्राइसेम, आर.एल.ई.जी.पी. इत्यादि प्रदान किए हैं। इसके साथ-साथ नगरीय बाह्य क्षेत्र में विकास ध्रुव केन्द्र की स्थापना करनी होगी। नगरीय क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों को भी बाह्य क्षेत्रों में स्थानान्तरित कर दिया जाना चाहिए। इससे दो फायदे होंगे।[7]

1. नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव कम होगा।
2. प्रदूषण स्तर में काफी कमी आएगी।

इन उपायों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करके ही हम इन समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं।

विचार-विमर्श

शहरीकरण विकास प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का परिवर्तन आर्थिक विकास का एक मजबूत मापदंड है। पिछड़े हुए स्थिर समाज में, शहरीकरण की प्रक्रिया लगभग धीमी है क्योंकि शहर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार देने में सक्षम नहीं हैं। हालांकि, शहरों में ग्रामीण आबादी का तेजी से पलायन केवल रोजगार पाने के उद्देश्य से है और इस स्थिति में पूंजी गहन उद्योगों के बजाय श्रम गहन उद्योगों पर जोर दिया जाता है। इसके विपरीत, शहरीकरण की गति धीमी हो जाती है जब कुल जल स्तर के अनुपात में शहरी आबादी बहुत उच्च स्तर तक पहुँच जाती है। यह स्थिति कुल 30 देशों में सामने आई है, जिन्हें विकसित औद्योगिक देश कहा जाता है। विवरण शहर क्षेत्रों के भौतिक विस्तार या इसके क्षेत्र, जनसंख्या आदि में वृद्धि को 'शहरीकरण' कहा जाता है। यह एक वैश्विक बदलाव है। भारत दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 08 डिग्री 04 मिनट से 37 डिग्री 06 मिनट उत्तर और 68 डिग्री 07 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में है। भारत का कुल क्षेत्रफल - 32,87,263 वर्ग किमी उत्तर (जम्मू और कश्मीर) से दक्षिण (कन्याकुमारी) तक है, भारत की कुल लंबाई 3,214 किलोमीटर है जबकि भारत की चौड़ाई पूर्व (अरुणाचल प्रदेश) से पश्चिम (गुजरात) तक है। 2,922 किमी। भारत की कुल भूमि सीमा 15,200 किमी है जबकि तटीय रेखा 7,516 किमी है।[8]

नगरीकरण की विशेषताएं :

1. बड़े शहरों में उद्योगों का केंद्रीकरण दिखाई दे रहा है।



2. शहरीकरण शहर बनने की प्रक्रिया है।
3. शहरीकरण की प्रक्रिया में, नए शहर बनते हैं और महानगरों का जन्म होता है।
4. कम जगह में ज्यादा लोग रहते हैं।
5. शहरीकरण की प्रक्रिया के दौरान, शहरों में रहने वाले लोग शहरी जीवन शैली को आत्मसात करते हैं।
6. शिक्षितों की संख्या का अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक है।
7. अनौपचारिक रिश्ते औपचारिक संबंधों में परिलक्षित होते हैं।
9. विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं।
10. औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। [7]

परिणाम

भारत में नगरीकरण :

20 वीं सदी की पहली छमाही भारत के लिए आर्थिक ठहराव की अवधि रही है। परिणामस्वरूप, शहरीकरण की गति बहुत अधिक नहीं थी। 1911 में कुल शहरी आबादी केवल 11 प्रतिशत थी, जो 1941 में बढ़कर 14 प्रतिशत हो गई। इस प्रकार, शहरी आबादी की वृद्धि 30 वर्षों में केवल 3 प्रतिशत थी। 1951 की जनगणना में शहरी आबादी कुल जनसंख्या का 17.3 प्रतिशत थी। इस वृद्धि का कारण वास्तविक नहीं था, बल्कि अधिक संख्यात्मक था, क्योंकि 1951 की जनगणना ने शहर की बहुत उदार परिभाषा को अपनाया था। 1961 में, शहर की परिभाषा को फिर से कस दिया गया था। इसलिए, 1951-1961 के बीच शहरी आबादी में केवल 0.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इस प्रकार 1961 में शहरी आबादी कुल जनसंख्या का 18 प्रतिशत हो गई। 1971 में अपनाए गए शहरी क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार, एक क्षेत्र को शहर क्षेत्र होने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा -

1. स्थान नगर निगम, नगर निगम, छावनी या अनुसूचित नगर क्षेत्र होना चाहिए।
2. अन्य सभी स्थानों के लिए न्यूनतम जनसंख्या 5,000 होनी चाहिए।
3. कम से कम 75 प्रतिशत पुरुष कामकाजी आबादी को गैर-कृषि गतिविधियों में संलग्न होना चाहिए।
4. जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति वर्ग किमी होना चाहिए।

1971 की जनगणना में दिए गए शहर के क्षेत्र की परिभाषा कुछ हद तक दृढ़ है, लेकिन अन्य देशों की तुलना में यह परिभाषा अभी भी काफी अच्छी है। उदाहरण के लिए - जापान में, 30,000 से अधिक की आबादी वाले स्थानों को शहर माना जाता है। इसके बावजूद, भारत में शहरी आबादी की परिभाषा कुल जनसंख्या का 23.3 प्रतिशत थी, जो 1991 में बढ़कर 25.7 प्रतिशत हो गई। जनगणना के अनुसार, 2001 तक, भारत की 27.81% आबादी शहरों में रहती थी। 2011 तक, यह 31.16% था।

भारत में, औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया दूसरी योजना में ही शुरू हुई, लेकिन शहरी आबादी में वृद्धि तीसरी योजना तक कुछ खास नहीं हो पाई। यह ज्ञात है कि भारी औद्योगिकीकरण की नींव दूसरी और तीसरी योजना में रखी गई थी लेकिन इसने भारी और बुनियादी उद्योगों पर विशेष जोर दिया। भारी और बुनियादी उद्योग पूंजी प्रधान हैं। इस प्रकार, उनकी रोजगार क्षमता काफी सीमित है। यही कारण है कि उनका विकास गांवों में उत्पन्न जनशक्ति को अवशोषित नहीं कर सका, जिसके कारण अर्थव्यवस्था प्रभावित नहीं हुई। इसलिए, औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया जो शुरू की गई थी,



उसमें तेजी नहीं लाई जा सकी। परिणामस्वरूप, तेजी से औद्योगिकीकरण नहीं हो सका। इसके अलावा, 1971 की जनगणना में शहरी क्षेत्र की अधिक सख्त परिभाषा के कारण, शहरीकरण में प्रतिशत वृद्धि भी कम हो गई थी।[6]

भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति:

संयुक्त राष्ट्र की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में दुनिया की आधी आबादी शहरों में रह रही है और 2050 तक भारत की आधी आबादी महानगरों और शहरों में रहने लगेगी। भारत में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है और तब भी विश्व स्तर पर कुल आबादी का 70% शहरों में रह रहा होगा।

आंकड़ों के मुताबिक, 2001 तक, भारत की 27.81% आबादी शहरों में रहती थी। 2011 तक, यह 31.16% था। मुंबई महानगर भारत में सबसे बड़ी शहरी आबादी है। मुंबई की जनसंख्या 2001 में 1 करोड़ 24 लाख थी जो 2011 में बढ़कर 1 करोड़ 84 लाख हो गई। दिल्ली की जनसंख्या 1 करोड़ 10 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 63 लाख हो गई। इसी तरह, बेंगलुरु की शहरी आबादी 2001 में 84 लाख 43 हजार थी, जो 2011 में बढ़कर 84 लाख 99 हजार हो गई। चेन्नई की जनसंख्या 80 लाख 46 हजार से बढ़कर 86 लाख 96 हजार हो गई। हैदराबाद की जनसंख्या 67 लाख 31 हजार से बढ़कर 77 लाख 49 हजार हो गई। अहमदाबाद की जनसंख्या 55 लाख 77 हजार से बढ़कर 63 लाख 52 हजार हो गई। इसी तरह, 2001 से 2011 के बीच पुणे की जनसंख्या 31 लाख 24 हजार से बढ़कर 50 लाख 49 हजार हो गई।

भारत में शहरीकरण की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। शहरी आबादी जो 1901 में 2 करोड़ 56 लाख थी, 1951 में बढ़कर 6 करोड़ 24 लाख हो गई। इस प्रकार 1901 में यह 2 करोड़ 56 लाख हो गई, यह 1951 में बढ़कर 6 करोड़ 24 लाख हो गई। इस प्रकार, 1901 और 1951 के बीच, शहरी आबादी 3.68 मिलियन की वृद्धि हुई। जबकि 1951 और 1981 के बीच, शहरी आबादी में 91.71 मिलियन की वृद्धि हुई। इसी तरह, 1981-1991 के बीच शहरी आबादी 5 करोड़ 77 लाख बढ़ गई। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि औद्योगिकीकरण से शहरी आबादी में आवश्यक वृद्धि हुई है, भले ही विकास धीमा हो। 2001 की जनगणना के अनुसार, शहरी आबादी 28.53 मिलियन थी जो कुल आबादी का 27.8 प्रतिशत है।

1901 और 2011 के बीच भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति:

1 लाख से अधिक आबादी वाले प्रथम श्रेणी के शहरों में शहरी आबादी का अनुपात, जो 1901 में 25.7 प्रतिशत से बढ़कर 65.2 प्रतिशत हो गया, यह दर्शाता है कि शहरी आबादी का रुझान बड़े शहरों में केंद्रित होने जा रहा है। दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में, शहरी आबादी का सापेक्ष अनुपात लगभग 1901 और 2001 के बीच था, यह 25-28 प्रतिशत था। लेकिन तुलना में, कक्षा IV, V और VI श्रेणी के शहरों में जनसंख्या के सापेक्ष अनुपात में तेज कमी आई और 1901 में 47.2 प्रतिशत से घटकर 1991 में केवल 11.7 प्रतिशत हो गई। 2011 में भारत में कुल शहरी जनसंख्या का प्रतिशत बढ़कर 31.16 हो गया।

[5]

प्रथम श्रेणी के शहर प्रशासनिक और सामान्य आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित हुए। उद्योग, परिवहन, व्यापार और वाणिज्य और प्रशासनिक और उदार सेवाएं भी इन शहरों में केंद्रित हैं। इस श्रेणी के शहरों में जनसंख्या की एकाग्रता का कारण यही है। इसके अलावा, जो शहर दूसरी श्रेणी की ऊपरी सीमा तक पहुंच गए हैं, वे प्रथम श्रेणी में प्रवेश करते हैं। इसके प्रमाण में, यह कहा जा सकता है कि 1951 में, जहां 74 शहर पहली श्रेणी में थे, 1991 में उनकी संख्या बढ़कर 296 हो गई, जो 1951 के सापेक्ष लगभग तीन गुना है। नतीजतन, 1951 में 275 लाख लोग थे प्रथम श्रेणी के शहरों में रहते हुए, जबकि 1991 में उनकी संख्या बढ़कर 1388 लाख हो गई, यानी यह 405 प्रतिशत बढ़ गई। इसी तरह, 2001 की जनगणना में शहरों और कस्बों की कुल संख्या 5161 थी, जो 2011 में बढ़कर 7936 हो गई।

नगरीकरण के प्रभाव :



1. ग्रामीण जीवन पर प्रभाव :

शहरीकरण ने ग्रामीण जीवन को प्रभावित किया है। शहर की सुविधाओं और उद्योग उन्मुख व्यवसायों, शिक्षा आदि के लिए ग्रामीण शहर की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

2. जीवन में कृत्रिमता :

शहरीकरण के कारण आज जीवन में वास्तविकता नहीं है। शहरीकरण से पहले, मानव उच्च विचारों के 'सरल जीवन' में विश्वास करता था, लेकिन इसका झुकाव कृत्रिमता की ओर है। कृत्रिमता अब मानव जीवन में आ गई है, अब उसने उपस्थिति और लालित्य में अधिक विश्वास करना शुरू कर दिया है।

3. सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन :

शहरीकरण के परिणामस्वरूप, सामाजिक मूल्य अब बदल रहे हैं। यह शहरीकरण का एक सामाजिक प्रभाव है। व्यक्तिवादी जीवन मूल्यों में सामूहिकता की भावना लगातार कम हो रही है। जीवन में नैतिकता और विश्वास की कमी है और स्वार्थ की भावना बढ़ रही है।

4. धार्मिक जीवन पर प्रभाव :

शहरीकरण का धार्मिक जीवन पर भी व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। धार्मिक मान्यताएं, परंपराएं, रीति-रिवाज आदि एक तरह से बदल गए हैं। अब अंधविश्वास को जन्म देने वाले तत्वों को खत्म किया जा रहा है। शिक्षा की मदद से, वैज्ञानिक और तर्कसंगत सोच अब विकसित हो रही है।

5. मनोरंजन का व्यवसायीकरण :

ग्रामीण समाज में मनोरंजन का उद्देश्य कभी पैसा नहीं रहा है, ग्रामीण समाज में मनोरंजन का उपयोग तनाव को दूर करने और एक साथ बैठने के लिए किया जाता है। लेकिन शहरीकरण में मनोरंजन का उद्देश्य पैसा रहा है।

6. महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन :

शहरीकरण के प्रभावों के कारण महिलाओं की स्थिति बदलने लगी है। वह अब घर के अंदर अपनी यौन भूमिकाओं तक सीमित नहीं है। आर्थिक रूप से, बल्कि वह आत्मनिर्भर होने लगी है। अब शिक्षा और राजनीति जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है।

7. हमारी कमी महसूस करना :

शहरीकरण के कारण अब हम भावना में कम होने लगे हैं। नागरिकायन ने व्यक्तिवाद को जन्म दिया है। हर कोई केवल अपने हित के बारे में सोचता है।[4]

8. सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन :

शहरीकरण के प्रभाव के कारण, परिवार और विवाह में निरंतर परिवर्तन होता है। अब संयुक्त परिवार प्रणाली एकल परिवार प्रणाली में बदल रही है। शहरीकरण के प्रभावों के कारण, व्यक्तिवादी सोच बढ़ने लगी है।

9. सेवा क्षेत्रों का विकास :

शहरीकरण की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप शहरी आबादी के प्रबंधन के लिए सेवा क्षेत्रों का विकास हुआ है। कई प्रकार की सरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं में वृद्धि की गई, जैसे; अस्पताल, पुलिस, अदालतें, शैक्षणिक संस्थान, गैर-सरकारी संस्थान आदि।



निष्कर्ष

नगरीकरण की समस्या :

स्वास्थ्य समस्याएं और शहरीकरण :

तेजी से शहरीकरण और बढ़ती शहरी आबादी को स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान की दिशा में बड़ी चुनौतियों के रूप में देखा गया है। यह अनुमान है कि 1990 और 2025 के बीच विकासशील देशों में शहरी आबादी तीन गुना बढ़ गई होगी और

यह कुल आबादी का 61 प्रतिशत हो जाएगा। इस बढ़ती शहरी आबादी के मद्देनजर स्वास्थ्य संबंधी कई चुनौतियों जैसे पानी, पर्यावरण, हिंसा और चोट, गैर-संचारी रोगों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा, तंबाकू के उपयोग, अस्वास्थ्यकर आहार, शारीरिक निष्क्रियता और महामारी के प्रकोप से जुड़े जोखिम और खतरे कम चुनौतीपूर्ण नहीं हैं।[3]

पर्यावरणीय चुनौती :

पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर शहर एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं क्योंकि शहर के विकास के लिए हरित क्षेत्र की बलि दी जा रही है। जलवायु परिवर्तन ने कई शहरों के अस्तित्व को चुनौती दी है, खासकर समुद्र तटीय शहर अब मानव निर्मित आपदाओं से अछूते नहीं हैं। इसके अलावा, तेजी से तकनीकी विकास शहरों में कई पारंपरिक व्यापारिक समूहों के लिए खतरा बन जाता है क्योंकि यह पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है।

शहरों में बढ़ती झुग्गी बस्तियाँ :

देश के सभी प्रमुख शहरों और महानगरों में बड़ी संख्या में झुग्गी बस्तियों का गठन किया गया है। उनमें रहने वाले लोग शहरी आबादी से संबंधित उच्च और मध्यम वर्ग की कई जरूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन वे न केवल गरीबी के शिकार हैं, बल्कि बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं।

यातायात की समस्या :

हर शहर में बेतरतीब यातायात एक गंभीर समस्या बन गई है क्योंकि सार्वजनिक परिवहन सेवाएं लगभग समाप्त हो गई हैं। शहर में रहने वाले अमीर लोग अपनी शक्ति और समृद्धि का प्रदर्शन करने के लिए यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं और इससे बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाएं होती हैं।

कुछ अन्य समस्याएं

हमारे देश का लगभग हर शहर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। निजीकरण और स्वास्थ्य सेवाओं के व्यावसायीकरण ने शहरों में असमानता पैदा कर दी है।

शहरों की सड़कों पर गड्ढे, सीवर प्रणाली की कमी और जल भराव, बिजली, पानी और संचार सुविधाओं के अव्यवस्थित रूप के कारण समस्याएं शहरी जीवन को इतना अधिक समस्याग्रस्त बना देती हैं कि मात्र कई शहरों में जाने के बारे में सोचा जाना दूभर हो जाता है।

शहर भी तुलनात्मक रूप से अपराध से अधिक असुरक्षित हैं ... कंक्रीट के जंगल में रहने वाले लोग अपने पड़ोसी को भी नहीं जानते हैं।

भावनात्मकता, संचार की खाई और विषयगतता शहरी आबादी के जीवन का हिस्सा बन गई है।



नवउदारवाद और वैश्वीकरण के बाद, गाँव अब केवल खाद्य, श्रम और कच्चे उत्पादों के आपूर्तिकर्ता बन गए हैं। शहर आधुनिकीकरण और उपभोक्तावादी सभ्यता को दर्शाते हैं और अधिकांश गाँव अपने अस्तित्व के लिए इन शहरों से जुड़े हुए हैं। शहरीकरण, औद्योगीकरण, सामाजिक गतिशीलता और प्रवासन की प्रक्रिया में वृद्धि हुई है और एक नई पीढ़ी ने गाँवों से शहरों की ओर पलायन करना शुरू कर दिया है।

इस तरह हम देखते हैं कि भारत में बढ़ते शहरीकरण के कारण कई समस्याएँ पैदा हुई हैं। इन समस्याओं के पीछे मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या है। भारतीय शहरों में पुरानी परंपरा के अनुसार, परिवारों के लिए रहना बहुत मुश्किल है क्योंकि आधुनिक समय में तेजी से और मूलभूत परिवर्तन हो रहे हैं। पुरानी परंपरा कृषि समाज के अनुसार है। शहरी परंपरा और ग्रामीण परंपरा में इसका तीव्र विरोध है। यह स्वाभाविक है कि प्रौद्योगिकी और शहरी समाजों में, नए प्रतिमान विकसित होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी संस्था, संगठन का मुख्य उद्देश्य मानवीय जरूरतों को पूरा करना है। वे संस्थान जो किसी भी समय मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं, वे हैं: यह समाप्त होता है। शहरों के विकास के लिए, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कई रोजगार के अवसर पैदा किए हैं - जैसे नेहरू रोजगार योजना, टिसम, आरएलईजीपी। आदि प्रदान किए गए हैं। इसके साथ ही शहरी बाहरी इलाकों में विकास पोल केंद्र स्थापित करना होगा। शहरी क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों को भी बाहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। इससे शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव कम होगा और प्रदूषण के स्तर में काफी कमी आएगी। इन उपायों को सफलतापूर्वक लागू करने से ही हम इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं।[8]

संदर्भ

1. अधिवास भूगोल, डॉ. रामयज्ञ सिंह, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद, उत्तरप्रदेश
2. सांस्कृतिक भूगोल, डॉ. गायत्री प्रसाद, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, उत्तरप्रदेश
3. नगरीय भूगोल, डॉ. सुरेश चन्द्र बंसल, मिनाक्षी पब्लिकेशन, नई दिल्ली
4. भारत में नगरीय समाज, रिया खत्री, कैलाश पुस्तक भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश
5. सामाजिक भूगोल, डॉ. एस. डी. मौर्य, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, उत्तरप्रदेश
6. नगरीय समाज शास्त्र, डॉ. वी. एन. सिंह, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, नई दिल्ली
7. G. S. Mohanty, Social and Cultural Geography, New Delhi
8. जनसंख्या भूगोल, डॉ. चतुर्भुज मामोरिया, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, उत्तरप्रदेश